contained in their 42nd Report on 'Review of the functioning of National Institutes established for different types of disabilities'.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

MR. CHAIRMAN: Now, Matters raised with permission. Shri Khiru Mahto — Demand to reschedule Rajdhani Express running between New Delhi to Ranchi.

Demand to reschedule Rajdhani Express running between New Delhi to Ranchi

श्री खीरू महतो (बिहार) : महोदय, मैं आपके संज्ञान में देते हुए, माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि राँची राजधानी एक्सप्रेस, जो राँची से चलकर नयी दिल्ली आती है और नयी दिल्ली से राँची जाती है, उसमें जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए इसके समय को घटाया जाए। यह जो 5 बजे खुलती है, उसको 3 बजे किया जाए, ताकि वह समय पर, 9.00-9.30 बजे नयी दिल्ली पहुँच सके।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

अभी यह 11.00, 11.30 या 12.00 बजे तक पहुँचती है। मैं आसन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे इसको सुधारें एवं इसका समय चेंज करें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) and Dr. V. Sivadasan (Kerala).

माननीय श्री राजीव शुक्ला जी - Concern over poor status of undertrials.

Poor state of under-trials

SHRI RAJEEV SHUKLA (Chhattisgarh): Sir, I rise to bring to the attention of this august House the alarming state of undertrials in India and the imperative need for judicial reforms in the light of the 78th Report of the Law Commission and data from the National Crime Report Bureau. Over the past decade, the undertrial population

has consistently risen, peaking in 2021, with 76 per cent of all prison inmates being undertrials in 2020, as per the NCRB. The concerns surrounding undertrials are multi-faceted, from the disproportionate arrest of resourceless individuals to the prevalence of violence and abuses in jails. The criminalisation by prison authorities leading to potential fatalities adds a critical dimension to this crisis. सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश भर में जितने कैदी हैं, उनमें से 76 परसेंट अंडर ट्रायल हैं। अदालतें इसमें 4-5 साल ले रही हैं, वे कोई फैसला नहीं करती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज, संजय किशन कौल जी ने कहा कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वे लोगों को जमानत दें। वे 4 साल बाद उनको फ्री करते हैं, acquittal करते हैं, रिहा करते हैं। इसमें उनकी जिन्दगी के 4 साल बरबाद हो जाते हैं। सर, ज्युडिशियरी में अंडर-ट्रायल्स की समस्या बहुत बड़ी है और ज्युडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने कई बार यह बात कही है। ज्युडिशियल रिफॉर्म्स होते नहीं हैं। क्रिकेट में रिफॉर्म, हॉकी में रिफॉर्म, मेडिकल काउंसिल में रिफॉर्म - सब चीजों में ज्युडिशियरी कहती है कि रिफॉर्म करो, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं करो। यानी ज्युडिशियरी में कोई रिफॉर्म नहीं हो, जैसा चल रहा है, वैसा ही उनका सिस्टम चलता रहे। कॉलेजियम सिस्टम, जैसा है चलता रहे; जज जैसे बनते हैं, बनते रहें और किसी चीज में अपने यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं हो, जबकि बाकी जगहों पर जस्टिस खुद इतना डिले करते हैं कि अभी 76 परसेंट अंडर-ट्रायल्स हैं। वे तमाम कैदी जो बाद में छूट जाते हैं - जब उनका अपराध साबित नहीं होता, तो वे रिहा हो जाते हैं, लेकिन तब तक वे जेलों में पड़े रहते हैं। 80-90 साल की बेचारी महिलाएँ वहाँ बन्द हैं, जो कि एक चिड़िया भी नहीं मार सकतीं, लेकिन बेवजह के आरोपों में वे बन्द हैं। उनको बाद में रिहा करते हैं। इसलिए यह बहुत गम्भीर समस्या है।

सर, मैं लॉ मिनिस्टर से, भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस समस्या का कोई निदान निकालें और ये जो अंडर-ट्रायल्स हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन वे डिले की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, इसका कोई रास्ता निकालें, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member: Shrimati Phulo Devi Netam (Chhattisgarh), Shri N.R. Elango (Tamil Nadu), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Vandana Chavan (Maharashtra), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu).

Now, Dr. Santanu Sen — Demand for inspection by teams of Central Government in different States to check the implementation process of different Government projects.